Condition of SSI units

454. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MNISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of SSI Units have either closed down or are at the verge of closure after the imposition of levies in current year's Budget and SSI units represented against these levies;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take to save the SSI from imminent closure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) A number of Federation and Associations of small scale units have in their representations expressed fear that the imposition oflevies in the current year's Budget May result in closure of a number of small scale units resulting in large scale unemployment of workers. However,, from the reports received so far there is no concrete evidence to prove that a number of SSI units have closed down or are on the verge of closure on account of imposition of levies in the current Budget.

(c) The Government is providing various facilities and incentives to ensure continued growth of this sector wnile a small percentage of units may be facing difficulties ties and getting closed, the overall growth rate achieved by this sector is satisfactory.

औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य

455. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1994 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "सी.एम.आई.ई. सीज इंडियाज इंडस्ट्रियल पिक अप शार्ट आफ टार्गेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1994–95 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तय की गई औद्योगिक विकास की दर की प्राप्ति की भी संभावना नहीं है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य प्रावकलन क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :
(क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा समग्र औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) सी.एस.ओ.. (केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन) द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान के अनुसार 1993–94 के दौरान समग्र औद्योगिक विकास दर 3.0% है।

लघु उद्योग विभाग द्वारा बजट आबंटन का उपयोग

456. श्री राम जेठमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान बजट में लघु उद्योग विभाग हेतु निर्धारित धनराशियों के लिए स्वीकृति दिए जाने के बावजूद इन राशियों को उपयोग में नहीं लाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो 1991–92, 1992–93, और 1993–94 के वार्षिक बजटों में आवंटित की गई राशियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विभाग द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आवंटित राशियों का पूरा-पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.अरुणाचलम) :: (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान निधियों के प्रयोग और उक्त वर्षों में बजट आबंटन के ब्यौरे विवरण–I में तथा आबंटित राशियों का पूर्ण प्रयोग न किए जाने के कारणों का उल्लेख विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993-94 के दौरान लघु उद्योग विभाग के बजट आबंटन तथा योजनागत स्कीमों के वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :

(रु० लाख में)

वर्ष	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
1991-92	35379.00	28659.97
1992-93	33142.00	30234.75
1993-94	36192.00	31657.42

विवरण II

1991–92, 1992–93, 1993–94 के दौरान लघु उद्योग विभाग द्वारा योजनागत धनराशि (आवंटनों) का प्रयोग न करने के कारणों का ब्योरा

1. सक्षम प्राधिकरणों अर्थात् ई०एफ०सी०इत्यादि से अनुमोदन न मिल पाने के कारण योजनाओं के विभिन्न हिस्सों का कार्यान्वित नहीं किया जा सका।।

2. एस०आई०एस०आई०/आर०टी० सी० स्तर पर रिक्त पदों के कारण सीडो के अधीन बचत।

3. सीडो के अधीन विस्तार केन्द्र बन्द होने के कारण लघु उद्योग सेवा संस्थानों और शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों की कार्यशालाओं के लिए नई मशीनों की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है।

Setting up of Tool Room-Cum-Training Centre at Jaipur

457. **SHRI RAMDAS AGARWAL:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of India have taken any final decision for giving Central assistance for setting up Tool-Room-Cum Training Centre at Jaipur, the total project cost of which is worked out to be Rs. 562.00 lakhs;

(b) whether Government of Rajasthan requested for Central fund/assistance to the tune of Rs. 225.00 lakhs and Rs. 337.00 lakh through UNDP assistance on the sme lines as has been provided by Government of India in the case of Central Institute of Tool Design, Hyderabad and Institute of Design for Electrical Measuring Instruments, Bombay;

(c) what is the present stage of approval of the project and how long it will take for the Centre to take a decision on State Government's request sent on 6th July, 1993 for setting up of above-mentioned Tool Room-Cum-Training Centre at Jaipur; and

(d) if the reply to part (a) above be in negative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) Government of Rajasthan requested for central fund/assistance to the tune of Rs. 89.25 lakhs (Non-recurring Rs. 25.65 lakhs and Recurring Rs. 63.60 lakhs) and Rs. 982.15 lakhs through UNDP or Japanese assistance